P-16

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार 17 मार्च 2016

P-16

किसान असली-नकली

कैसी विडंबना है कि एक तरफ देश में खेती-बाड़ी पर संकट बढ़ता ही जा रहा है, किसान का जीना मुहाल हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ गिने-चुने लोगों की कृषि-आय उछालें मार रही है। सच्चाई यह है कि खेती से हर साल करोड़ों-अरबों कमाने वाले ये किस्मत के धनी अपनी बेहिसाबी कमाई को खेती से हुई आमदनी बताकर टैक्स चोरी कर रहे हैं। खेती से होने वाली कमाई पर देश में कोई टैक्स नहीं लगता, लिहाजा यह काले पैसे को सफेद करने का बेहतरीन जरिया बनी हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में कहा कि टैक्स से बचने के लिए अपनी आमदनी को 'कृषि-आय' दिखाने वाले कुछ जाने-माने लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। साथ में उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि अगर इसमें विपक्ष के किसी सदस्य का नाम आए तो इसे राजनीतिक दुश्मनी साधने की कवायद न समझा जाए। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू द्वारा कृषि आय की आड़ में टैक्स चोरी का मुद्दा उठाने पर जेटली ने यह बात कही। लगभग संपूर्ण विपक्ष ने इस संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह मामला उठाया था और सरकार से कार्रवाई की मांग भी की थी। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 में 6.50 लाख किसानों ने करीब 2 हजार लाख करोड़ की कमाई की, जो देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। यह रिपोर्ट एक आरटीआई आवेदन पर मिले सरकारी जवाब के आधार पर तैयार की गई है। इस संबंध में पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी दायर हुई है, जिसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सक्रिय हो गया है। उसने आयकर रिटर्न में एक करोड़ रुपये से अधिक की कृषि आय के दावों की सच्चाई की जांच शुरू कर दी है। कृषि आय को कर के दायरे में लाया जाए या नहीं, यह एक पुरानी बहस रही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विजय एल. केलकर की अध्यक्षता वाली कर सुधार समिति ने कृषि पर आयकर लगाने की सिफारिश की थी। इसके पहले प्रो. चांचू समिति भी यही राय व्यक्त कर चुकी थी। पर राजनीतिक स्तर पर एक आम सहमति चली आ रही है कि खेती पर टैक्स न लगाया जाए। इसका फायदा कुछ संपन्न किसानों को भी मिलता रहा है। लेकिन इसकी आड़ में बड़ा शिकार वे लोग कर रहे हैं, जिनका खेती से कोई लेना-देना ही नहीं है। प्रायः हरेक दल में कई ऐसे छोटे-बड़े नेता हैं, जो अपना धंधा खेती ही बताते हैं। पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे यह जाना जा सके कि उनका खेती से कोई रिश्ता है या नहीं। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का यह खुला खेल अर्थव्यवस्था के लिए भारी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि खेती को एक पवित्र क्षेत्र मानने की मानसिकता से अब ऊपर उठा जाए। किसानों को टैक्स छूट का फायदा जरूर मिले, लेकिन कृषि कार्य को ठीक से परिभाषित किया जाए और एक निश्चित सीमा के बाद खेती से कमाई का ऑडिट भी किया जाए, ताकि असली और नकली किसान का भेद उजागर हो सके।

खेती और काला धन

17-3-16

प्रभारी, समाचार पत्र यूनिट